[Shri Shinkre]

At the same time, we are also sure that the Prime Minister will not do or allow himself to do anything that is not becoming to the self-respect and dignity of this country.

With these words, I would only say in conclusion that may God bless him with the success that he so richly deserves.

Shri Muhammad Ismail (Manjeri): We heartily endorse the programme which the Prime Minister has announced before us and we wholeheartedly wish him god-speed and satisfying and brilliant success in his endeavours in his visit to the various countries.

श्री यशपाल सिंह : मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब कि कल रात के 9 बजे तक पाकिस्तान रेडियो ने यह एलान किया है कि सिर्फ काश्मीर के मसले पर वार्त्ता करने के लिए ताशकन्द की यह मीटिंग हो रही है और आज तक पाकिस्तान के रवैये में कोई फर्क नहीं आया है, पाकिस्तान ने हमारे सरस्वती नामक जहाज को जब्त किया, फिर उसको डिस फिगर करके उसके ऊपर रजिया नाम लिख लिया, तो इस हालत में जो मसला संगीनों के द्वारा हल होना है वह ताशकन्द की कोठियों में कैसे हल हो जायेगा ?

Shri Lal Bahadur Shastri: Sir, I have nothing much to say, except that I would like to express my gratefulness to hon. Members for the kind sentiments expressed by them. I am also glad to notice that generally our stand has been endorsed by all the Leaders of the Opposition.

In regard to Kashmir, I need not say anything at all, because I have made my position and the position of the Government absolutely clear. But if you will permit me, I would say that I am specially grateful to Dr. Lohia for the constructive suggestions he has made.

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा एक शब्द और कहना चाहता हूं कि अयूब साहब से हिन्दी में बात कीजिएगा ।

Mr. Speaker: I am glad that, by and large, every party has extended support to our Prime Minister in his mission and has wished him success. On behalf of those who have not spoken, I extend our support to him and wish him god-speed. On behalf of those in the country outside also, I wish him every success in the mission he is undertaking. He carries with him the support of everyone in the country.

16.37 hrs.

RESOLUTION RE: NATIONAL AND EMOTIONAL INTEGRATION—*contd.*

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, मैं इस बात का निवेदन कर रहा था कि जब हमारे देश पर मुसीबत आती है तो एक प्रकार की ऊपरी एकता दिखाई पड़ती है । उसकी वजह से हम कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे देश में वस्तुत: एकता उत्पन्न हो गई है । एकता दो प्रकार की हो सकती है । एक नारंगी जैसी जो ऊपर से देखने में तो एक मालूम पड़ती है लेकिन उसके भीतर फाकें अलग-अलग होती हैं और दूसरी खरबूजे जैसी एकता जिसमें ऊपर तो अलग अलग धारियां दिखाई पड़ती हैं लेकिन वस्तुत: वह भीतर से एक है । अभी हमारे देश की जो एकता है वह कई मानों में नारंगी जैसी एकता है । लेकिन हमारा यह आदर्श होना चाहिये, कि हम अपने देश के भीतर वास्तविक एकता उत्पन्न करने की कोशिश करें ।

16.38 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

कि 1961 में हमारे भूतपूर्व माननीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया था और वह सम्मेलन अनेक महत्वपूर्ण निश्चयों पर पहुंचा था। उस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन ने कहा था :

तं वर्षं भारतं नाम भारती यत्र संततिः।

इस देश में इसकी सीमा के अन्दर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह भारतीय हैं, और इस सीमा के भीतर जो निवासी रहते हैं उन निवासियों में जो विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं, जो विभिन्न जातियों के हैं और जो देश के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं उनमें एकता स्थापित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जाय।

उसी सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि जब तक हमारे देश से साम्प्रदायिकता, जातीयता, प्रदेशवाद, भाषा-वाद और संकीर्ण मनोवृत्तियों का उन्मूलन नहीं होता है तब तक हमारे देश में वास्तविक एकता कायम नहीं हो सकती है। मैं सरकार का ध्यान उस सम्मेलन में स्वीकृत विभिन्न प्रस्तावों की ओर इस लिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने समझ बूझकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। इस दृष्टि से मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस सम्मेलन ने इस बात का जिक्र किया था कि राष्ट्रीय एकता एक प्रकार से मनो-वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसी दृष्टि से यह बात बतायी थी कि अगर हम सचमुच इस देश में राष्ट्रीय और भावात्मक एकता कायम करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, इस देश की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि इस देश की जो शिक्षा पद्धति है उस में परिवर्तन लाया जाय, बुनियादी तौर पर परिवर्तन लाया जाय इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाय। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इतने वर्षों के बाद भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, अब तक हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी किसी नीति का निर्धारण नहीं कर सकी है। यद्यपि राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने प्रधान मंत्री के सभापतित्व में ये प्रस्ताव स्वीकृत किये थे फिर भी, इतने वर्षों के बाद भी, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उसी सम्मेलन में इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया था कि सारे देश में जब तक सन्तुलित रूप से आर्थिक विकास नहीं होता है तब तक हमारे देश की एकता की नींव गहरी नहीं हो सकती है लेकिन मैं बड़े अदब के साथ सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी भी हमारे देश के क्षेत्रीय विकास में बड़ा असन्तुलन है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान मैं कुछ आंकड़ों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अभी नेशनल कौंसिल आफ ऐप्लाईड ऐकोनामिक रिसर्च ने अपनी पुस्तक **करेंट प्राबलम्स आफ प्लाइड ऐकोनामी** में इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि इस देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 261 रु० है और विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय में बड़ा भारी भेद है। असम में जब कि प्रति व्यक्ति औसत आय 306 रुपये है तो बिहार में प्रति व्यक्ति की केवल 207 रुपये है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा अन्तर, केवल औसत आय का यह अन्तर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि राष्ट्रीय नीति के रूप में हमने इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार का क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं होना चाहिये फिर भी यह बड़े दुख की बात है कि तीन योजनाओं के बाद भी क्षेत्रीय आय की दृष्टि से, क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से, सारे देश में अभी भी बड़ा भारी अन्तर वर्तमान है।

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

प्रति व्यक्ति की श्राय में गरीब श्रौर श्रमीर की श्राय में इस देश में जो बड़ा भारी श्रसन्तुलन है, श्रन्तर है उसकी श्रोर भी मैं सरकार का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहूंगा ।

श्रभी सरकार ने जो एकाधिकार श्रायोग की स्थापना की थी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित है श्रौर उस रिपोर्ट में बड़े विस्तार के साथ यह दिखाया गया है कि इस देश में किस प्रकार से श्रार्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता जा रहा है । इसी प्रकार से कुछ वर्ष पूर्व प्रोफेसर महालोनबीस की श्रध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसने राष्ट्रीय श्राय के वितरण के सम्बन्ध में जो श्रध्ययन श्रौर श्रांकड़े प्रस्तुत किये हैं उससे भी ऐसा सिद्ध होता है कि न केवल प्रति व्यक्ति की श्राय में बड़ी भारी श्रसमानता है न केवल क्षेत्रीय श्राय में श्रसमानता है बल्कि उसकी वजह से हमारे देश में जो राजनैतिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं श्रौर श्रार्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण की वजह से हमारे देश की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता जा रहा है उसके कारण यह भी सम्भव नहीं है कि हमारे देश में वास्तविक एकता उत्पन्न हो सके । इसलिए इस बात की तरफ सरकार का ध्यान रखना जाना श्रत्यन्त श्रावश्यक है ।

इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो श्रसन्तुलन है उसकी श्रोर भी श्राकृष्ट करना चाहता हूं । जबकि पूरे देश में साक्षरों की श्रौसत संख्या के भी नीचे वाले कुछ प्रदेश हैं । ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में श्रसन्तुलन है कि दिल्ली में साक्षरों की संख्या करीब 52 प्रतिशत: है श्रौर जम्मू काश्मीर में केवल 10 प्रतिशत है । ऐसी श्रसमानता, ऐसा श्रसन्तुलन शिक्षा के क्षेत्र में है या चाहें जिस किसी क्षेत्र से लें, जब तक ऐसा श्रसन्तुलन हमारे देश में बना रहेगा तब तक वास्तविक एकता सम्भव नहीं है । इसी प्रकार से भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, साम्प्रदायिक भावना को लेकर श्राये दिन हमारे देश में एसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, वातावरण को इस प्रकार से विषाक्त बनाने की कोशिश की जाती है जिसकी कि वजह से कभी कभी श्रशान्ति उत्पन्न हो जाती है । कानून श्रौर शान्ति, व्यवस्था का मामला बड़ा टेढ़ा हो जाता है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस बात की श्रोर श्राकृष्ट करना चाहता हूं । श्रौर जो विरोधी दल में हैं उनको भी यह याद दिलाना चाहता हूं कि उनका भी यह कर्त्तव्य है कि वे देश में शान्ति श्रौर व्यवस्था बनाये रक्खें । हम में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जहां देश को बात हो भारत की एकता की बात हो उसमें कोई किसी प्रकार के मतभेद को जगह नहीं होना चाहिए श्रौर देश की एकता खंडित न होने पावे । उसके लिए हमें बराबर प्रयत्न करना चाहिए ।

यह सही है कि चूंकि दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर हमारे देश का विभाजन हुश्रा तो उस का विष इतना गहरा चला गया, इतना गहरा हमारे जीवन में बैठ गया जिसमें श्रभी भी ऐसी प्रवृत्तियां देश में समय समय पर उभरती रहती हैं जिन की वजह से देश की एकता खतरे में पड़ जाती है । उन्हीं मनोवृत्तियों से प्रेरित होकर श्रभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के श्रवांछित काम करते हैं श्रौर वह चाहते है कि इस देश के श्रौर भी टुकड़े हों । ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों को, ऐसे सिद्धान्तों को श्रौर ऐसी विचारधाराश्रों को हमें रोकने का प्रयत्न करना होगा श्रौर रोकने का यह प्रयत्न केवल कानून बना कर नहीं किया जा सकता है । इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, श्रार्थिक क्षेत्र में, प्रशासकीय क्षेत्र में श्रौर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बुनियादी तौर पर परिवर्तन करना पड़ेगा । हमें श्रपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा श्रौर ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिसमें हम इस बात का श्रनुभव कर सकें,

अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर सकें, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। धर्म, साम्प्रदायिक आदि, हर एक क्षेत्र में हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि हम भारतीय पहले हैं, हिन्दु, मसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि बाद में हैं। हम भारत के रहने वाले पहले हैं बिहार और बंगाल के रहने वाले बाद में हैं। हम भारतीय पहले हैं और हम इस जाति या उस जाति के सदस्य बाद में हैं। हम भारतीय पहले हैं उत्तर और दक्षिण के बाद में हैं। हम भारतीय पहले हैं हिन्दी भाषी, अंग्रेज़ी भाषी या तामिल भाषी, बंगला भाषी बाद में हैं। जब तक ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारे देश में बराबर ऐसा वातावरण रहेगा जिसकी वजह से जब भी संकट आयेगा तब थोड़ी देर के लिए तो हम एक हो जायेंगे ऐसा मालूम पड़ेगा कि हम एक हो गये लेकिन वह वास्तविक एकता नहीं होगी। मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश में एक ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से विकास कार्यों में जो जन सहयोग सरकार को मिलना चाहिए वह जन-सहयोग सरकार को नहीं मिल पाता है। योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात हो या सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की बात हो या और प्रकार के दुष्प्रभाव हों, और प्रकार की कमियां हों, और प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अभाव ही उन सब से लड़ने के लिए जो मनोबल चाहिए वह शक्ति और मनोबल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है।

अभी लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है **प्लानिंग एण्ड दी पीपुल**, उसमें यह बात बड़े विस्तार के साथ सिद्ध की गई है आंकड़ों के बल पर इसे सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि जो योजनाएं और विकास के जो कार्य सरकार की ओर से होते रहते हैं उनमें जनता का सहयोग नहीं मिलता रहा है। यह जन सहयोग कैसे प्राप्त हो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर राष्ट्रीय भावना प्रबल होती, अगर लोग इस बात को अनुभव करते कि चीन का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान के खतरे का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि अनाज की पैदावार बढ़ायी जाय, यह आवश्यक है कि कारखानों में उत्पादन बढ़ाया जाय, यह आवश्यक है कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने दायित्व का पालन किया जाय तो इससे निश्चय ही हमारे देश का स्तर ऊंचा होता, हमारे देश के निवासियों के जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा होता और हमारी जो इतनी बड़ी शक्ति है, जनसंख्या की दृष्टि से, हमारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनका हम पूरी तरह से उपयोग कर पाते। इस सम्बन्ध में मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं :—

'वे देश शान्ति के सबसे शत्रु प्रबल हैं,
जो बहुत बड़े होने पर भी दुर्बल हैं,
हैं जिनके उदर विशाल, बांह छोटी है,
भोथरे दांत, पर, जीभ बहुत मोटी है।
औरों के पाले जो अलज्ज पलते हैं,
अथवा शेरों पर लदे हुए चलते हैं।
सिंहों पर अपना अतुल भार मत डालो,
हाथियों, स्वयं अपना तुम बोझ संभालो।
यदि लदे फिरे, यों ही, तो पछताओगे।
शव मात्र आप अपना तुम रह जाओगे।
यह नहीं मात्र अपकीर्ति, अनय की अति है।
जानें, कैसे सहती यह दृश्य प्रकृति है।"

जिस देश में 48 करोड़ लोग रहते हों जिसमें प्राकृतिक सम्पदा भरी हुई हो, जिस देश की भूमि इतनी उपजाऊ हो, जिस देश में अन्य प्राकृतिक साधनों की कमी न हो, जिस देश के निवासियों में बुद्धि का अभाव न हो उस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि लोगों को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन न मिले, अपनी रक्षा के लिए जिस देश को बराबर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

उससे अधिक हमारे लिए राष्ट्रीय ग्लानि की बात दूसरी कोई और नहीं हो सकती है और जब भी ऐसे मौके आयेंगे हम इस बात का बराबर अनुभव करेंगे कि हमें दूसरों की ओर ताकना पड़ता है। इसलिए मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हूं कि चाहे खाद्य स्थिति की बात हो, चाहे हथियारों की बात हो या दूसरे विषयों की बात हो, हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। हमने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो कर जो त्याग किया, जो बलिदान किया, उसी के कारण हमने आजादी प्राप्त की। अभी मोर्चे पर हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान किया, उसकी वजह से इस देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ, जिसमें, थोड़ी देर के लिए और ऊपर से ही सही, एकता की भावना दिखाई पड़ती है। फिर हमें अपने सार्वजनिक जीवन और अपने प्रशासन में भी उसी त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित हो कर कदम उठाना पड़ेगा। यह तभी संभव है कि जब हमारे देश में वह शक्ति आए, वह तेज आए, वह आत्म-विश्वास पैदा हो, जिसके बल पर हम आगे कदम बढ़ा सकें, आगे बढ़ सकें।

इस दृष्टि से हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में और हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं में जो अभाव दिखाई पड़ता है, जो कमियां और त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं, उनको दूर करने के लिए, मेरा विश्वास है, माननीय गृह मंत्री महोदय उचित और आवश्यक कदम उठायेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस संकल्प को पेश करते हुए अन्त में डा० इकबाल की दो पंक्तियों को उपस्थित करना चाहता हूं :

ऐ तायरे लाहूती ! उस रिज्क से मौत अच्छी।
जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही ॥

हम बराबर दूसरे देशों की ओर देखते हैं—किसी मामले में इंग्लैंड की ओर, किसी मामले में रूस की ओर और किसी मामले में अमरीका की ओर देखते हैं, लेकिन हम अपने भीतर की शक्तियों को खोजने और उनको काम में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक हममें यह आत्म-विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को पेश करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए और देश की राष्ट्रीय और भावात्मक एकता को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

धन्यवाद।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House is of opinion that with a view to make India nationally and emotionally integrated, necessary steps be taken to eradicate all disintegrating forces, namely communalism, casteism, regionalism, narrow linguism etc., from every walk of our life."

There are several amendments.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that with a view to creating healthy atmosphere congenial to the growth of national integration, stringent measures be taken against all fissiparous tendencies arising out of perverse outlook based on communalism, casteism, regionalism, narrow linguism etc." **(1)**

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :—

"इस सभा की राय है कि भारत में राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के राज्यों का पुनर्गठन करके उन्हें पांच अथवा छः इकाइयों में विभक्त किया जाये, जिससे प्रदेशवाद, साम्प्रदायिकता, संकीर्ण भाषावाद आदि तत्वों का उन्मूलन किया जा सके।" (2)

Shri Balakrishnan (Koilpatti): I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that with a view to make India nationally and emotionally integrated and to achieve the objects of democratic socialistic society, drastic steps be taken to eradicate casteism, untouchability, regionalism and linguism." (3)

Shri Mohammad Koya (Kozhikode): I beg to move:

That in the resolution,—

after "communalism" *insert*—

"intolerence towards minorities". (4)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :—

"इस सभा की राय है कि भारत में राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता स्थापित करने की दृष्टि से निम्न कदम उठाये जायं—

(क) पिछड़ा वर्ग जिस में हरिजन, आदिवासी, हिन्दू समाज की छोटी जातियों, ईसाई मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों का पिछड़ा हिस्सा और औरतें आदि शामिल हैं, के लिए सभी क्षेत्रों में 60 प्रति शत जगह आरक्षित की जाये ;

(ख) समूह के पैमाने पर अन्तर्जातीय और अन्तर्धर्मीय सहभोज, राखी बन्धन आदि कार्यक्रमों को अपनाया जाये ;

(ग) जाति के नाम वाली किसी भी शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को कोई सरकारी सहायता, परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप में न दी जाये ;

(घ) सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर जनेऊ, चोटी और दाढ़ी आदि के खिलाफ सामाजिक अभियान चलाया जाये ;

(ङ) अन्तर्वर्णीय, अन्तर्धर्मीय और अन्तर्जातीय शादी करने वालों को सरकारी नौकरी में विशेष अवसर दिये जायं ; और

(च) योजनाओं के स्थान, सीमा आदि से सम्बन्धित अन्तर्प्रान्तीय झगड़ों का, न्याय तथा बराबरी हासिल करने के सिद्धान्त के आधार पर, निष्पक्ष अदालत द्वारा फ़ैसला किया जाये।" (5)

Shri Muthiah (Tirunelveli): I beg to move:—

That for the original resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the Government should take positive steps to achieve national unity and integration at all levels,

[Shri Muthiah]

political, social, economic and educational, and eradicate the evils of casteism, communalism, regionalism and linguism." (6)

Mr. Deputy-Speaker: Amendment No. 8 in the name of Shri Muhammad Ismail is the same as No. 4 which has already been moved. Dr. Mahadeva Prasad is not here.

This Resolution and the amendments are before the House. We will resume this discussion on the next day.

श्री मधु लिमये : चूंकि यह प्रस्ताव अगले सत्र में आयेगा, इसलिये यह प्रस्ताव और तरमीमें उस समय फिर से परिचालित की जायें, क्योंकि माननीय सदस्यों के पास उस समय ये नहीं रहेंगी ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Home Minister.

16.5 hrs.

STATEMENT *RE*: POSTPONEMENT OF GENERAL ELECTIONS IN ORISSA

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Sir.

Following the introduction of President's rule in Orissa on the 25th February, 1961, the mid term elections to the Orissa Legislative Assembly took place in June, 1961 and the date appointed for the first meeting of the Orissa Legislative Assembly was 21st August, 1961. Therefore, in normal course the Orissa Assembly would continue up to the 20th August, 1966.

The General Election to a legislative assembly which does not syncronise with the country-wide general elections always presents a number of problems and difficulties. In the present case as the present term of the Orissa Legislative Assembly is going to expire on the 20th August, 1966, the interval of time between that date and the country-wide general elections of February—March 1967 is small being only about six months. It is to be considered whether for this small interval we should face the problems and difficulties which I may presently mention. In the first place, there is the question of duplication of expenditure to be incurred by the Government as well as the candidates and the political parties, first for the general election to the legislative assembly and then again for the general elections to Parliament. In the second place, we should not overlook the heavy burden that will fall upon the administrative machinery if a general election is to be held for the Orissa Assembly in 1966 and then a few months thereafter for the Lok Sabha in the early part of 1967. In the third place, we should bear in mind the inconvenience of the electorate also.

For all these reasons some of the political parties functioning in Orissa, such as the Praja Socialist Party and the Bhartiya Jana Sangh are opposed to the holding of a separate general election for the Orissa Assembly. The Swatantra Party, have, however, passed a resolution early in August 1965 urging the holding of the general election for the Orissa Assembly in March—April 1966. This, it will be noted, was before the hostilities with Pakistan and the commencement of Chinese intrusions.

Finally, there is the emergency. And because of that even the by-elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies have been postponed. We feel it would not be desirable to dissipate our time, energy and money on a separate general election which would give rise to sharp political divisions inevitable in a general election.

Upon all these considerations, we feel that in the wider interests of the nation, it would be desirable to postpone the separate general election for the Orissa Legislative Assembly till